PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 | Issue : 19 | Mumbai | Friday, 12 June to 18 June 2026 | Weekly | Pages : 8 | Price : 3 Rs.

संक्षिप्त खबरें

जम्मू-कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्लीः रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में चल रही और प्रस्तावित रेलवे परियोजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अनंतनाग में नया व्यावसायिक ठहराव (स्टॉपेज) देने का फैसला किया गया। रेलवे मंत्रालय का कहना है, अनंतनाग में वंदे भारत के ठहराव से यात्रियों, पर्यटकों और व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे कश्मीर के प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक अनंतनाग की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, वंदे भारत सेवा ने जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा को अधिक तेज, सुविधाजनक और आरामदायक बनाया है। बेहतर रेल सेवाओं का लाभ स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी मिल रहा है।

एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के शासन के मील के पत्थर की सराहना की

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (10 जून) को रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 4,399 दिन लगातार पद पर रहकर वे भारत के सबसे लंबे समय तक निरंतर सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कई ऐतिहासिक सुधार देखे हैं। साल 2014 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद उन्होंने जन-धन योजना के जरिए देश के करोड़ों गरीबों को बिना किसी न्यूनतम राशि के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। इसके बाद उनके कार्यकाल में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला, जबकि जीएसटी जैसे बड़े टैक्स सुधार ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत में कुछ सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों की देखरेख की है। इनमें से कई फैसलों ने देश के आर्थिक ढांचे, सुरक्षा सिद्धांत, कल्याणकारी वितरण तंत्र और राजनीतिक विमर्श को पूरी तरह से बदल दिया है।

राम मंदिरः शायद किसी भी मुद्दे का भाजपा के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन से अधिक प्रतीकात्मक महत्व नहीं था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, राम मंदिर का निर्माण तेज हो गया, जो अंततः जनवरी 2024 में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के रूप में संपन्न हुआ।

तीन तलाकः 2019 में, संसद ने तत्काल तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया। सरकार ने इस कदम को लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया, और तर्क दिया कि इसने मुस्लिम महिलाओं को मनमाने ढंग से तलाक की प्रथाओं के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की है।

अनुच्छेद 370: 5 अगस्त, 2019 को सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को समाप्त कर दिया। (शेष पेज-3 पर देखें)

योगी सरकार का बड़ा फैसला

तीन तलाक-एसिड अटैक पीड़िताओं को मिलेगा घर और हेल्थ कवर

लखनऊः महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक कुरुतियों और आपराधिक कृत्यों से प्रभावित महिलाओं को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आवास और हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रदान करने की तैयारी कर रही है. योगी सरकार इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही निराश्रित महिलाओं को भी इन योजनाओं के दायरे में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने इस संबंध में

कार्रवाई तेज कर दी है. विभाग ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं के साथ-साथ निराश्रित महिलाओं का विस्तृत और सत्यापित डेटा एकत्र कर रहा है, ताकि पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। सरकारी स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देशों और शासनादेश को तैयार करने की प्रक्रिया भी जारी है. प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। योगी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला जानकारी के अभाव या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रिपल तलाक या एसिड अटैक जैसी परिस्थितियों का सामना कर चुकी और जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, ऐसी महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए।

तमिलनाडु सीएम बनने के बाद

पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिले विजय

नई दिल्ली : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की सोनिया गांधी से यह पहली मुलाकात थी, जबकि राहुल गांधी उनकी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले थलापति विजय की कांग्रेस नेतृत्व के साथ यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब लोकसभा का मुख्य विपक्षी दल अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। विजय की वजह से तमिलनाडु में कांग्रेस की दशकों पुरानी साथी डीएमके नाराज चल रही है। ऐसे में राहुल और सोनिया गांधी की विजय

से मुलाकात तमिल वेत्री कड़गम (TVK) के लिए INDIA गठबंधन के रास्ते खोल सकता है। हालांकि, विजय पहले ही कांग्रेस के प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित कर चुके हैं। तमिलनाडु में वह कांग्रेस के साथ सत्ता में हैं इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा की एक सीट भी कांग्रेस को दी है। बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार दिल्ली आए थलापति विजय प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वापस चले गए थे। (शेष पेज-5 पर देखें)

नीट-यूजी री-एग्जाम

संसदीय समिति के सामने सरकार का वादा-'अब नहीं होगी कोई चूक'

नई दिल्ली : नीट-यूजी की तीन मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों और मानसिक तनाव से जूझ रहे लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने संसदीय स्थायी समिति को आश्वासन दिया है कि 21 जून को होने वाली नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली इस समिति के सामने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी और नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के अध्यक्ष अभिजात सी. सेठ ने अपना पक्ष रखा। (शेष पेज-5 पर देखें)

रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला

नौसेना को मिलेंगे 449 करोड़ के एडवांस ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम जैमर्स

नई दिल्ली : नौसेना को मजबूत और सुरक्षा करने की दृष्टि से रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने बेंगलुरु की ASSPL कंपनी के साथ 449 करोड़ रुपए में उन्नत क्षमता वाले ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम जैमर्स बनाने का समझौता किया है, जो कि आने वाले समय में नौसेना के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इन सैटेलाइट जैमर्स के लगने के बाद दुश्मन देश का कोई भी जहाज भारत के समुद्री रडार के भीतर आकर नुकसान नहीं पहुंचा सकता ह। इन सैटेलाइट जैमर्स में लगने वाला 75 प्रतिशत सामान स्वदेशी होगा, जो आत्मनिर्भर भारत

का बड़ा उदाहरण है. रक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु की अकॉर्ड सॉफ़्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (ASSPL) कंपनी के साथ भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम (ECGNSS) जैमर्स की खरीद के लिए यहा समझौता किया है। यह समझौता 'खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)' श्रेणी के तहत 10 जून को दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ। इस प्रणाली की क्षमताओं में प्रतिद्वंद्वी GNSS रिसीवर के सैटेलाइट सिग्नल अधिग्रहण और ट्रैकिंग प्रदर्शन को कमजोर करना और सिग्नल स्पूफिंग जैमिंग शामिल हैं। जो कि नौसेना के जहाजों द्वारा मल्टी-डैंजर वाले वातावरण में सुरक्षित संचालन की राह बनाएगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो अपने आसपास की वायरलेस रेंज में समस्या खड़ी कर देता है। (शेष पेज-5 पर देखें)

संपादकीय

न्याय का द्वार कितना समान ?

कानून की समानता और न्याय तक पहुँच का प्रश्न

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का आश्वासन देता है। परन्तु सार्वजनिक विमर्श में समय-समय पर यह प्रश्न उठता है कि क्या न्याय तक पहुँच भी सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। न्यायपालिका लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। फिर भी न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता, मुकदमों की अवधि, विधिक सहायता की लागत तथा उच्च न्यायालयों तक पहुँच की व्यावहारिक कठिनाइयाँ अनेक नागरिकों के लिए चुनौती बनी रहती हैं। परिणामस्वरूप कभी-कभी यह धारणा बनती है कि संसाधनों से सम्पन्न पक्ष न्यायिक प्रक्रिया का अधिक प्रभावी उपयोग कर सकता है। समसामयिक चर्चित प्रकरणों से एक महत्वपूर्ण विधिशास्त्रीय पाठ भी प्राप्त होता है। पहला, अभियोजन द्वारा आरोपित धाराओं की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों के मध्य संतुलन का प्रश्न, जो जमानत के प्रारम्भिक परीक्षण (prime facie assessment) को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। दूसरा, न्यायालय का आदेश अंततः किसी भी विधिक कथा का निर्णायक दस्तावेज होता है। न्यायालय व्यक्तियों की लोकप्रियता, प्रभाव अथवा सामाजिक स्थिति पर नहीं, बल्कि तथ्यों, साक्ष्यों और विधिक तर्कों के आधार पर निर्णय देता है। इसी कारण न्याय केवल निष्पक्ष होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका निष्पक्ष दिखाई देना भी आवश्यक है। किसी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि उसका सबसे सामान्य नागरिक भी न्याय के द्वार तक उतनी ही सहजता से पहुँच सके जितना कोई प्रभावशाली व्यक्ति। कानून की समानता तभी सार्थक है, जब न्याय तक पहुँच की समानता भी सुनिश्चित हो।

पाठ्यक्रमों का सुनियोजित विस्तार जरूरी

देश में रह-रहकर बौद्धिक वर्ग में डीकोलोनाइजेशन यानी वि-उपनिवेशीकरण की चर्चा छिड़ती रहती है, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी वि-उपनिवेशीकरण की मुहिम छिड़े तो उसका आधार भी भारतीय होना चाहिए। हमें इस तथ्य को पहचान कर भारत में समकालीन उच्च शिक्षण संस्थानों और उनके उत्पादों, अनुसंधान प्रयासों एवं स्नातकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में देखा जाए तो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को नवाचारों के माध्यम से सजीव करने की आवश्यकता तो बहुत दिनों से महसूस की जाती रही है, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। यह प्रवृत्ति देशज विकास के प्रयासों में सदैव बाधक ही रहेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी देश की शैक्षणिक प्रणाली पर औपनिवेशिक पकड़ को समाप्त करना एक कठिन कार्य सिद्ध हो रहा है। वर्तमान में कई भारतीय संस्थानों के पाठ्यक्रम भारतीय परिप्रेक्ष्य की वास्तविकताओं या इसकी समस्याओं के ज्ञान को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करते। उच्च संस्थानों की प्रणालियों में भारतीय ज्ञान के वि-उपनिवेशीकरण के प्रयासों को तभी स्पष्ट और सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा सकेगा, जब छात्रों को यह सिखाया जाए कि मौलिकता की राह पर कैसे चलें? उन्हें भारतीय परिस्थितियों के लिए विशेष और विशिष्ट समाधान की दिशा में सोचने के लिए भी शिक्षित करना होगा। भारतीय ज्ञान की वर्तमान व्यवस्था के वि-उपनिवेशीकरण से ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति संभव हो सकेगी। अब नवोन्मेषी विचारों और कार्यक्रमों की शुरूआत करने से पहले सोचने के लिए ज्ञान मीमांसकीय रूप से स्वतंत्र होना होगा। ज्ञान मीमांसकीय मुक्ति मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता को जन्म देती है। शिक्षा के उच्च संस्थानों ने भारतीय विचार-दृष्टि की गतिशीलता पर अपनी पकड़ खो दी है। इसका एक विशेष कारण है ज्ञान को समायोजित करने के लिए भारतीय भाषाओं को विकसित करने में विफलता। आज भी अंग्रेजी प्रामाणिक भाषा है और ज्ञान की दुनिया में उसी का वर्चस्व है। मन में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में सोचते हुए उन विचारों को अंग्रेजी में उल्था कर प्रस्तुत करना समयसाध्य ही नहीं, बहुधा निष्प्रभावी एवं अप्रामाणिक भी सिद्ध होता है। मौलिक सोच का अवसर इसलिए भी जाता रहता है कि हम अपने विचार और उसकी कोटियां विदेश से आयातित किए हुए हैं और उसमें 'फिट' किए बगैर सोचने-विचारने की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो पाती है। अपने शिक्षण संस्थानों में होने वाले बौद्धिक प्रयासों, शिक्षण प्रक्रिया और अनुसंधान में भारतीय भाषाओं को संस्थागत रूप से न अपना पाना मौलिकता के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि कई देश जो तकनीकी प्रगति में छलांग लगा रहे हैं, आविष्कारों में प्रगति कर रहे हैं और अकादमिक उत्कृष्टता की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, वे ही देश हैं जिन्होंने अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को अपने अनुसार अनुकूलित एवं विकसित किया है। दुर्भाग्य से हमने अपने सोच को उन सीमाओं के भीतर ही सीमित करके बांध लिया है, जो पश्चिमी शिक्षा से विरासत के रूप में हमें मिला। साथ ही हम व्यावहारिक और उपयोगी विकल्प खोजने के लिए पर्याप्त उत्सुक भी नहीं हैं। चाहे जो भी हो, यूरोकेंद्रित ज्ञान माडल में डूबे रहने से हमारे विचारों का उपनिवेशीकरण लगातार बढ़ता रहा है और यह हमेशा देशज विकास के उन प्रयासों में बाधा भी उत्पन्न कर रहा है, जो आत्मनिर्भर देश की जरूरत है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण और समकालीन अनुसंधान और वैचारिक वास्तविकताओं में उन विचारों एवं सिद्धांतों के समावेश के अलावा, भारतीय विश्वविद्यालयों को भारतीय प्रतिभा और ज्ञान मीमांसा को ईमानदारी से चित्रित करने के लिए मौजूदा पाठ्यक्रमों और शैक्षिक कार्यक्रमों का सुनियोजित विस्तार करना होगा। तभी वे देश को सक्षम और तत्पर बनने में कामयाब हो सकेंगे। हमारे पाठ्यक्रम और उनकी मूल्यांकन पद्धति भारतीय विश्वदृष्टि के पीछे छिपे तर्क और उनकी समीक्षा पर प्रश्न पूछने और उनका विस्तार करने में सक्षम होने चाहिए। ये पाठ्यक्रम छात्रों और लोगों की रुचि को इस तरह से आकर्षित करने वाले होने चाहिए, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से चुनकर नाम गिनाने की कवायद की औपचारिकताएं मात्र न निभा रहे हों, बल्कि उनके माध्यम से सोचने के लिए प्रेरित हों। इस दिशा में आवश्यक है कि वे स्वयं अपनी और राष्ट्रीय चेतना का आह्वान भी कर सकें। भारतीय मनीषा और अवधारणाओं को सहज प्रासंगिक रूप से शिक्षा में शामिल करना होगा कि वे अतिरिक्त भार न बनकर हमारी आवश्यकताओं एवं चुनौतियों का सामना करने में हमें समर्थ बना सकें।

जनसंख्या वृद्धि दर में कमी से जुड़ी चिंता

भारत में पिछले कुछ दशक से धीरे-धीरे जनसंख्या वृद्धि दर की गति में कमी आ रही है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकीय रिपोर्ट के विश्लेषण से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे भविष्य में कुछ मामलों को लेकर अभी से ही चिंता बढ़ गई है। जनसंख्या वृद्धि दर में यदि गिरावट इसी तरह से कायम रही तो कुछ दशक के बाद देश में वयस्क आबादी कम हो जाएगी, जिससे श्रम बल का अभाव हो सकता है। ऐसे में हमें इस रिपोर्ट में छिपे संकेतों को समय रहते समझना होगा, ताकि उसी अनुरूप नीतियां भी बनाई जा सकें। भारत की प्रजनन क्षमता (फर्टिलिटी) की कहानी चुपचाप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा प्रकाशित 'सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024' में इसे विस्तार से बताया गया है। वस्तुतः यह दुनिया भर में आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों में से एक है- जो उस बात की पुष्टि करती है जिसे जनसांख्यिकी विशेषज्ञ वर्षों से ट्रैक कर रहे हैं। इसमें यह पाया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) गिरकर 1.88 पर आ गई है। आधिकारिक आंकड़ों में एक दशमलव तक पूर्णांकित (राउंड) करने पर इसे 1.9 दर्ज किया गया है। यह लगातार पांचवां वर्ष है जब भारत 2.15 के प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) से नीचे बना हुआ है। यह कोई मामूली सांख्यिकीय अपडेट नहीं है। यह एक संरचनात्मक जनसांख्यिकीय मील का पत्थर है, जिसके परिणाम आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, श्रम बाजार, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और सामाजिक ताने-बाने को आकार देंगे। संबंधित विशेषज्ञ इसे कई मायनों में चिंताजनक बता रहे हैं। प्रतिस्थापन क्यों मायने रखता है : कुल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट- टीएफआर) बच्चों की उस औसत संख्या को मापती है जो एक महिला अपने जीवनकाल में मौजूदा जन्म दरों के आधार पर पैदा करेगी। किसी भी समाज को बिना किसी बाहरी प्रवासन के, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी जनसंख्या को बनाए रखने और स्थिर रखने के लिए अपने टीएफआर को प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) पर या उससे ऊपर रखना आवश्यक होता है। वैश्विक स्तर पर यह प्रतिस्थापन स्तर पारंपरिक रूप से प्रति महिला 2.1 बच्चे माना जाता है। हालांकि भारत में यह आंकड़ा थोड़ा अधिक यानी 2.15 है। यह समायोजन भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात (सेक्स रेशियो एट बर्थ- एसआरबी) में लगातार और चिंताजनक विकृति के कारण आवश्यक है। कन्या भ्रूण हत्या सहित लिंग-चयनात्मक प्रथाओं ने जन्म के समय लड़कियों और लड़कों के अनुपात को बिगाड़ दिया है। वर्ष 2024 की एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार, भारत का एसआरबी प्रति एक हजार पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं, जिसमें वर्ष 2018 से 2020 की अवधि में रहे 907 के मुकाबले मामूली सुधार के रूप में दिख रहा है, लेकिन अभी भी लगभग 952 महिलाओं के प्राकृतिक अनुपात से काफी नीचे है। चूंकि हमारे देश में अब लड़कियां कम पैदा हो रही हैं, इसलिए जनसंख्या प्रतिस्थापन को बनाए रखने के लिए प्रति महिला अधिक जन्म की आवश्यकता होती है। 1.88 पर भारत का टीएफआर अब अपने खुद के प्रतिस्थापन (आरंभिक बिंदु) से 0.27 बच्चा नीचे है, और यह अंतर हर साल अधिक होता जा रहा है। यह सही है कि इस दर में पिछले चार दशकों में धीरे-धीरे ही सही, परंतु गिरावट दर्ज की है। वैसे यह कोई अपवाद नहीं है। भारत की प्रजनन क्षमता में उल्लेखनीय रूप से निरंतर गति से गिरावट आ रही है। वर्ष 1985 में राष्ट्रीय टीएफआर 4.3 था। तब से यह लगभग 0.06 प्रति वर्ष की दर से गिरा है, जिसमें कोई अचानक तेजी या उलटफेर नहीं देखा गया है। यह प्रवृत्ति उदारीकरण के दौर, मोबाइल क्रांति और इंटरनेट मीडिया के युग से पहले की है। यह निरंतरता अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो लोग भारत की प्रजनन क्षमता में गिरावट का मुख्य श्रेय स्मार्टफोन या इंटरनेट को देते हैं, उन्हें एसआरएस डाटा में इसका बहुत कम समर्थन मिलेगा। यह गिरावट पिछले लगभग चार दशक से धीरे-धीरे हो रहा है। यह गिरावट इन तकनीकों की बड़े पैमाने पर पहुंच से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी और स्थिर थी। हालांकि डिजिटलीकरण ने मौजूदा प्रवृत्तियों को मजबूत किया होगा, ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस कारण जनसंख्या में गिरावट शुरू हुई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गिरावट के पलटने का कोई संकेत नहीं है। यदि इसी गति से गिरावट जारी रही तो भारत का टीएफआर वर्ष 2031 तक लगभग 1.57 तक पहुंचने का अनुमान है, जो वर्तमान में अमेरिका के स्तर के समान है। उस बिंदु तक प्रतिस्थापन के सापेक्ष प्रजनन क्षमता का अंतर काफी बड़ा हो जाएगा और जनसांख्यिकीय गति (डेमोग्राफिक मोमेंटम) जो अभी भी एक बड़ी आबादी और बढ़ती जीवन प्रत्याशा द्वारा प्रदान किया जाने वाला बफर है- अंतर्निहित संकुचन (कमी) को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। एसआरएस 2024 डाटा से लिया जाने वाला शायद सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु सबसे सरल है: भारत कोई अपवाद नहीं है। भारत जिस प्रजनन संक्रमण का अनुभव कर रहा है- आर्थिक विकास, महिला शिक्षा और शहरीकरण के आगे बढ़ने के साथ तीव्र गिरावट- यह वही संक्रमण है जो जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, ब्राजील, ईरान और पश्चिमी यूरोप में देखा गया है। वर्ष 1985 से 2024 तक का भारत का संबंधित आंकड़ा प्रतिस्थापन स्तर से नीचे की प्रजनन क्षमता की ओर एक सीधी रेखा का वर्णन करता है।

पीपिल्स टाइम्स

विकसित भारत 2047

पीयूष गोयल ने मुंबई में की एआई आधारित रोजगार पहल शुरू

मुंबईः केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना देश के युवाओं के नेतृत्व, कौशल और दृढ़ संकल्प के बल पर ही पूरा होगा। मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने यह बात युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने वाले विभिन्न कौशल विकास और रोजगार उपक्रमों की शुरूआत करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री ने उत्तर मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी कौशल विकास केंद्र में कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का शुभारंभ किया। इसमें सौंदर्य क्षेत्र के लिए लॉरियल प्रशिक्षण केंद्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित अपना प्लेसमेंट केंद्र शामिल है। अपना केंद्र युवाओं को एआई की मदद से सही करियर चुनने, इंटरव्यू की तैयारी करने और आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने में मदद करेगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए एक बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब पर भी काम चल रहा है।

वैश्विक रोजगार और महिला सक्षमीकरण : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने युवाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र में जापानी जैसी विदेशी भाषाएं सीखकर युवा विदेशों में शानदार करियर बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश की प्रगति के लिए महिला सशक्तिकरण को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और दिव्यांग युवाओं को मिल रहा प्रशिक्षण देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है।

समाज के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी : मंत्री पीयूष गोयल ने कौशल विकास के लिए उद्योग जगत और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सीखे गए कौशल का उपयोग समाज की सेवा के लिए भी करें। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय युवाओं की ऊर्जा और सकारात्मक सोच आने वाले समय में देश को एक बेहद मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाएगी।

महाराष्ट्र के प्याज किसानों को राहत, छगन भुजबल का नाफेड को निर्देश

30 जून तक सीधे खरीदें दो लाख टन प्याज

मुंबईः बड़े आंदोलन के बाद सूबे के प्याज उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने नाफेड और एनसीसीएफ कृषि उपज मार्केट कमेटियों को किसानों से सीधे प्याज खरीदने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए खरीद लक्ष्य को 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते दिनों केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से दिल्ली में प्याज किसानों की समस्याओं का हल निकालने मुलाकात की थी। पिछले कई दिनों से प्याज के वाजिब समर्थन मूल्य और निर्यात के मुद्दे को लेकर राज्य के किसान आक्रामक हैं। किसान सही कीमत न मिलने के कारण अपनी उपज सड़कों पर फेंक रहे हैं या खेतों में फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा है। भुजबल ने पीएसएफ प्याज अभियान 2026-27 के तहत बैठक आयोजित कर अधिकारियों, मार्केट कमेटियों के पदाधिकारियों मार्गदर्शन किया। मंत्री भुजबल ने निर्देश दिया है कि मार्केट कमेटियां तुरंत प्याज खरीदने के सेंटर शुरू करें। साथ ही ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाएं। 1 जून तक केवल 1.55 मीट्रिक टन प्याज खरीदा गया है, जबकि लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन है। बेमौसम बारिश से उपज की गुणवत्ता पर असर पड़ा है, इसलिए केंद्र सरकार ने ग्रेड-ए के नियमों में ढील दी है। उपज को गुणवत्ता परीक्षण के दौरान बेवजह रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। यदि आवश्कता पड़ी तो राज्य सरकार प्याज खरीदने के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से बात करेगी।

मुंबई में 3 साल में बेस्ट बसों से 950 से ज्यादा एक्सीडेंट

मुंबईः ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, जनवरी 2023 और दिसंबर 2025 के बीच, BEST बसें 958 बड़े एक्सीडेंट में शामिल थीं, जिनमें 77 मौतें हुईं और 217 घायल हुए। कंपनी के सूत्रों ने बताया कि इनमें से 85% से ज्यादा एक्सीडेंट वेट-लीज बसों के कारण हुए, जिससे एक बार फिर उस ऑपरेटिंग मॉडल की ओर ध्यान गया जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। पिछले दिनों BEST कमेटी की मीटिंग में, चुने हुए प्रतिनिधियों ने सिस्टम के बारे में चिंता जताई और सुझाव दिया कि अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड में सुधार नहीं होता है तो वेट-लीज मॉडल को फिर से देखने की जरूरत हो सकती है। BEST कमेटी की चेयरपर्सन तृष्णा विश्वासराव ने कहा कि कंपनी ने वेट-लीज ऑपरेटरों को एक्सीडेंट कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है, यह देखते हुए कि वेट-लीज बसों में लोगों का भरोसा कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सेफ्टी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होता है तो कॉर्पोरेशन इस मॉडल को बंद करने पर विचार कर सकता है। वेट-लीज अरेंजमेंट के तहत, BEST ड्राइवरों के साथ बसें देने के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों को काम पर रखता है। इससे पैसे की तंगी से जूझ रही ट्रांसपोर्ट कंपनी को गाड़ियों में बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए बिना सर्विस बढ़ाने या घटाने में मदद मिलती है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बसों की सप्लाई, मेंटेनेंस और ऑपरेट करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिसमें ड्राइवर हायर करना भी शामिल है। हालांकि, BEST के पास पूरी सुपरवाइजरी ज़िम्मेदारी है और उसे यह पक्का करना है कि ऑपरेटर उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करें।कमेटी के सदस्यों ने प्राइवेट ऑपरेटरों पर बड़ी ज़िम्मेदारी डाली, यह आरोप लगाते हुए कि ड्राइवर को कम सैलरी मिलने से ऑपरेशनल और सेफ्टी से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

मुंबई में 19 हजार से ज्यादा जन्म प्रमाणपत्रों में किए गए बदलाव होंगे रद्द

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में साल 2024 से 2026 के बीच जन्म प्रमाणपत्रों में किए गए 19,734 संशोधनों (बदलावों) को रद्द करने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जन्म प्रमाणपत्र रद्द नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनमें नियमों के विपरीत किए गए बदलावों को हटाकर मूल रिकॉर्ड बहाल किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा आयुक्तालय, पुणे द्वारा जारी निर्देश में मुंबई के जिला रजिस्ट्रार और संबंधित अधिकारियों को इन मामलों की जांच कर मूल जन्म रिकॉर्ड को बहाल करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और महाराष्ट्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2000 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बड़ी संख्या में संशोधन किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 19,734 मामलों में से 16,528 मामलों में किसी प्रकार के सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जबकि 3,206 मामलों में दस्तावेज अधूरे पाए गए। इसी वजह से इन संशोधनों को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। यह मामला भाजपा नेता और महाराष्ट्र एसआईआर प्रमुख किरीट सोमैया द्वारा उठाए जाने के बाद चर्चा में आया था। सोमैया ने आरोप लगाया था कि कुछ जन्म प्रमाणपत्र ऐसे अस्पतालों के नाम पर जारी किए गए, जिनका अस्तित्व ही नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया था कि फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से पहचान संबंधी दस्तावेज हासिल किए जा सकते हैं।

एसआईटी कर रही जांच

■ मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई में फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़े कुछ मामलों की जांच अपराध शाखा की विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सौंपी गई है। बीएमसी के दो पूर्व स्वास्थ्य अधिकारियों पर बिना उचित सत्यापन के कुछ जन्म पंजीकरणों को मंजूरी देने के आरोप भी लगाए गए हैं।

मेयर रितु तावड़े ने दिए जांच के आदेश

■ वहीं मेयर रितु तावड़े ने इस साल जनवरी में एक समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि बांग्लादेशी नागरिकों को 267 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों की जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई करने और रिपोर्ट पुणे स्थित उप मुख्य रजिस्ट्रार को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

पेज-1 का शेष

एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के शासन के मील के पत्थर की सराहना की...

इस फैसले ने भाजपा की लंबे समय से चली आ रही वैचारिक प्रतिबद्धता को पूरा किया और यह मोदी के कार्यकाल के सबसे साहसिक राजनीतिक कदमों में से एक था।

यूपीआई और डिजिटल क्रांतिः भारत के डिजिटल परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। 2016 में एक छोटे से भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ UPI, आज भारत की खुदरा अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, इसने 200 बिलियन से अधिक लेनदेन संसाधित किए, जो देश की खुदरा डिजिटल भुगतान मात्रा का लगभग 85 प्रतिशत है, और लेनदेन का मूल्य 314 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। क्यूआर कोड अब इतने आम हो गए हैं कि किराने की खरीदारी और ईंधन से लेकर बिजली बिलों और सड़क किनारे के स्नैक्स तक हर चीज के लिए नकद की जगह डिजिटल भुगतान होने लगा है।

जैम ट्रिनिटीः जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) आर्किटेक्चर ने नागरिकों तक कल्याणकारी लाभ पहुंचने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। बैंक खातों, बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी को जोड़कर, सरकार ने सब्सिडी वितरण में होने वाले लीकेज को कम किया और अभूतपूर्व पैमाने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को संभव बनाया। यह मॉडल तब से डिजिटल गवर्नेंस में एक वैश्विक केस स्टडी बन गया है।

महिला आरक्षण बिलः महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना एक और बड़ा राजनीतिक क्षण था। यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, एक ऐसा सुधार जो राजनीतिक समर्थन के बावजूद दशकों से रुका हुआ था। जिससे महिलाओ का सत्ता मे भागीदारी बढ़ेगी।

जीएसटीः जुलाई 2017 में लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने राज्य और केंद्रीय करों के जटिल जाल को हटाकर एक एकल अप्रत्यक्ष कर ढांचा पेश किया। यह सुधार कई वर्षों से लंबित था, लेकिन मोदी सरकार इसे लागू करने में सफल रही। जीएसटी ने एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया और स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक बन गया।

स्टार्टअप इंडियाः जब मोदी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, तब भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने शुरूआती चरण में था। एक दशक बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक का घर है, जहां फिनटेक, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हजारों मान्यता प्राप्त स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इस पहल ने नवाचार और उद्यमशीलता को आर्थिक नीति के केंद्र में स्थापित करने में मदद की।

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारतः मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण के मुख्य विषय बन गए। मेक इन इंडिया पहल ने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने का प्रयास किया, जबकि आत्मनिर्भर भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान गति पकड़ी। सरकार ने घरेलू उत्पादन, सप्लाई-चेन के लचीलेपन और रणनीतिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इन कार्यक्रमों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा से लेकर सेमीकंडक्टर तक के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने में मदद की।

इंफ्रास्ट्रक्चरः भारत में हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे के आधुनिकीकरण, एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क और ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में तेजी से विकास हुआ है, खासकर दूर-दराज के इलाकों में जहां तक कभी रोड, बिजली नहीं पहुंची आज वह भी गाड़ियां स्पीड पकड़ चुकी है और घर रोशन हो चुकी है।

ग्लोबल डिप्लोमेसीः भारत ने सक्रिय कूटनीति, मजबूत अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और जी20 जैसे मंचों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाकर अपनी वैश्विक उपस्थिति को काफी मजबूत किया है। एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में, भारत ने जलवायु परिवर्तन, आर्थिक स्थिरता और बहुपक्षवाद जैसे मुद्दों पर दुनिया को एक नई दिशा दी है।

स्वच्छ भारत मिशनः स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर लॉन्च किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को पूरी तरह से स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए अनुदान राशि दिया गया ताकि हर घर शौचालय बन सके। जैसे ही मोदी ने लगातार कार्यकाल के लिए नेहरू के रिकॉर्ड को पार किया, यह मील का पत्थर केवल राजनीतिक धीरज से कहीं अधिक को दर्शाता है। यह एक ऐसे दौर का प्रतिनिधित्व करता है जिसके दौरान भारत ने कराधान, कल्याण, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय सुरक्षा, विनिर्माण और सांस्कृतिक नीति में व्यापक बदलाव देखे।

मुंबई-ठाणे को जाम से मिलेगी मुक्ति!

सीएम फडणवीस ने 22,611 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

मुंबईः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में कुल 22,611 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (MMR) में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के मकसद से घोड़बंदर रोड पर गायमुख से फाउंटेन होटल तक अंडरग्राउंड टनल और फाउंटेन होटल से भयंदर तक एलिवेटेड ब्रिज के लिए 17,036 करोड़ रुपए, और नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1अ और 2 के लिए 5,575 करोड़ रुपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भरोसा जताया कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लागू होने से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर और तेज हो जाएगा। कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजित पवार, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत और चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के साथ-साथ अन्य सीनियर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे।

अंडरग्राउंड टनल और एलिवेटेड ब्रिज को मंजूरी : इस भारी-भरकम बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 17,036 करोड़ मुंबई महानगर क्षेत्र की सड़कों को सुधारने पर खर्च किया जाएगा। गायमुख और फाउंटेन होटल के बीच 5.86 किलोमीटर लंबी, छह-लेन वाली अंडरग्राउंड टनल बनाई जाएगी और फाउंटेन होटल और भयंदर के बीच 9.58 किलोमीटर लंबा छह-लेन वाला एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट वेस्टर्न मुंबई को ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नासिक और पनवेल से जोड़ने के लिए तेज और सुविधाजनक कनेक्टिविटी देगा, साथ ही नेशनल हाईवे-48 तक पहुंच भी बेहतर करेगा।

घोड़बंदर रूट पर ट्रैफिक से मिलेगी राहत : यह प्रोजेक्ट घोड़बंदर रूट पर भारी गाड़ियों के बोझ और ट्रैफिक को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा, खासकर ठाणे और गुजरात जाने वाले ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्ते से डायवर्ट करके। यह प्रोजेक्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 'बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर' (BOT) मॉडल का इस्तेमाल करके लागू किया जाएगा। सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारों द्वारा 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' दी जाएगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रोजेक्ट एरिया के लिए MMRDA को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के तौर पर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

महाराष्ट्र पब्लिक एक्ट 2016 में बदलाव को मंजूरी

मुंबईः कैबिनेट मीटिंग में राज्य में नए कॉलेजों, विस्तार, नई फैकल्टी, करिकुलम और नए सब्जेक्ट, बैच वगैरह को फाइनल मंजूरी देने के हिसाब से एकेडमिक साल 2026-27 के लिए महाराष्ट्र पब्लिक एक्ट 2016 में बदलाव को मंजूरी दे दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। इस फैसले के मुताबिक, इस एक्ट के नियमों के मुताबिक नए कॉलेज या इंस्टिट्यूशन शुरू करने और उन्हें परमिशन देने की डेडलाइन 30 जून, 2026 होगी। इस एक्ट, 2016 में प्रस्तावित एक्सटेंशन कवि वाइस चांसलर कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी, रामटेक पर भी लागू होगा। कैबिनेट मीटिंग में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के नियमों के हिसाब से महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में बदलाव को मंजूरी दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 56वीं मीटिंग में, भारत सरकार ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के अलग-अलग सेक्शन में बदलाव किए हैं। मीटिंग में उन बदलावों को मंजूरी दी गई जो इन नियमों के हिसाब से सही हैं। इसके अनुसार, महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 में बदलाव किया जाएगा और इस बारे में ड्राफ़्ट को मंजूरी दी गई।

क्लस्टर योजना को 'महत्वपूर्ण सार्वजनिक आवास' का दर्जा

महाप्रीत की जगह MSRDC को मिली काम की जिम्मेदारी

ठाणेः ठाणे शहर में खतरनाक इमारतों में रहने वाले नागरिकों को तुरंत राहत देने के लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्लस्टर योजना को गति देने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोपरी, किसननगर और वागले एस्टेट की क्लस्टर परियोजनाओं को अब महाप्रीत से हटाकर एमएसआरडीसी को सौंप दिया जाएगा। ठाणे जिले में क्लस्टर परियोजनाओं को और अधिक गति देने के लिए सरकार इन्हें ह्वाइटल पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आवास (महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजना) घोषित करेगी। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री शिंदे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यह देश की पहली इतनी बड़ी समूह विकास (क्लस्टर डेवलपमेंट) योजना है। यह केवल एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्हें सुरक्षित घर का अधिकार देने वाला एक बड़ा बदलाव है। बुनियादी ढांचे के विकास में एमएसआरडीसी के बड़े अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि महाप्रीत से एमएसआरडीसी को काम सौंपने की जो भी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया जरूरी है, उसे बिना किसी देरी के तुरंत पूरा किया जाए। इसके लिए आवश्यक कानूनी कागजी कार्रवाई को भी तेज गति से निपटाने के लिए कहा गया है।

नवी मुंबई मेट्रो का विस्तार किया जाएगा

गौरव सिंह/नवी मुंबई

नवी मुंबईः मुंबई मेट्रोपॉलिटन इलाके में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए, घोड़बंदर रोड पर गायमुख से फाउंटेन होटल सबवे और फाउंटेन होटल से भायंदर एलिवेटेड ब्रिज के लिए 17,036 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही, नवी मुंबई मेट्रो रूट 1अ और रूट 2 के लिए 5,575 करोड़ रुपये के कुल 22,611 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की मीटिंग में मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लागू होने से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आसान और तेज हो जाएगा। पिछले दिनों मंत्रालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में गायमुख और फाउंटेन होटल के बीच 5.86 km लंबा छह लेन का अंडरपास और फाउंटेन होटल और भायंदर के बीच 9.58 km लंबा छह लेन का एलिवेटेड ब्रिज बनाने की लागत को मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट से वेस्ट मुंबई के ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नासिक, पनवेल

के साथ-साथ नेशनल हाईवे-48 तक तेज और आसान ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी। यह अंडरपास TBM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। इसका डायमीटर भी 14 मीटर होगा। इस टनल को लगभग पांच साल में पूरा करने का प्लान है। वसई क्रीक के पैरेलल चलने वाले एलिवेटेड ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। इस मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा अजीत पवार, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत, चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल और एडमिनिस्ट्रेशन के कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने CIDCO के नवी मुंबई मेट्रो रूट 1अ (सागर संगम से CBD बेलापुर) और मेट्रो रूट 2 (पेंढर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट T-4) प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। यह प्रोजेक्ट सागर संगम से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कुल 28 km का लगातार मेट्रो रूट देगा। इस एक्सटेंशन में रूट 1अ पर दो स्टेशन और रूट 2 पर 11 स्टेशन शामिल हैं। भविष्य में, इस मेट्रो सर्विस से हर दिन लगभग 12 लाख यात्रियों को फायदा होगा।

घोड़बंदर रूट पर बढ़ते ट्रैफिक और भारी गाड़ियों के दबाव को कम करने में यह प्रोजेक्ट अहम होगा। ठाणे और गुजरात की ओर जाने वाले ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डायवर्ट करना मुमकिन होगा।यह प्रोजेक्ट 'बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर' मॉडल के जरिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर लागू किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें 'वैलिडेट गैप फंडिंग' देंगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रोजेक्ट एरिया में MMRDA को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के तौर पर नियुक्त करने की भी मंजूरी दी।

Result Guarantee Above 90% or Money Back
If U R Not Joining Home Tuitions Then U R Missing Many Things
Mumbai's No.1 Premium Home Tuitions Academy
MUMBAI HOME & PRIVATE TUITIONS
1st to 10th ICSE / CBSE / IB / IGCSE / NIOS / State Boards
XI & XII Sci / Comm. IIT, NEET, MHT-CET
Engg, Degree, Diploma, B.Com, Bsc., BMS, MBA, Gmat, Cat, CET, English Speaking
Rajendra Deshmukh MANAGING DIRECTOR
Any Class Home Tuitions Across Mumbai
Get Admission in MBBS
NEET Qualified / Unqualified Fees 25 Lacs (Inc. Food Acc.)
ADMISSIONS OPEN
Branches : Andheri - Worli - Jogeshwari - Malad - Badar - Borivali - Virar
Thane - Vashi - Nerul - Kharghar - Ambernath - Badlapur
Home Tuitions Benefits
Contact : 902 902 9222 / 80 80 80 34 12 / 8446642380 / 9209128153
https://www.mumbaihometutors.com

PRIME KEYS PROPERTIES
Beyond Dreams
BUY | SELL | RENT
FLATS • SHOPS • BUNGALOWS
LANDS • REDEVELOPMENT
Trusted Property Consultant
Residential & Commercial Deals
Best Market Price Assistance
Contact:
+91 9167378057
Your Dream Property, Our Priority

DR. ZUBER SHAH HOSPITAL & POLYCLINIC
Ambernath (W), Maharashtra
Nursing Home Reg. No.: THN-C274*
FACILITIES AVAILABLE
24x7 Emergency Care - Immediate Critical Support
Diabetology & Advanced Diabetic Care
Fever Treatment (Dengue, Chikungunya, Malaria, Influenza)
Cardiology Checkup & ECG Facility
General Medicine Consultation
Vaccination & Immunization Services
Minor Surgical Procedures
OPD & IPD Care Available
Complete Health Checkups
24 HOURS EMERGENCY SERVICE AVAILABLE
DR. ZUBER S. SHAH
M.B.B.S (Reg. No. 2024020955)
Cert. in Diabetology & Emergency Medicine
+91 9323594085 / 8237304085 | Buvapada, K B Road, Ward No. 2/2, Ambernath West, Thane
Woolen Chawl OPD : 8:00 pm to 11:30 pm | OPD Amber Care : 8149477110

हेल्दी रहना है तो डेली डाइट में शामिल करें ये इम्युनिटी बूस्टर जूस

■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। बदलते मौसम, गलत खानपान और बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारी इम्युनिटी कमजोर हो जाती है। ऐसे में प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर जूस का सेवन शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। ये जूस न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि शरीर को ऊर्जा भी देते हैं और कई बीमारियों से बचाने में मदद करते है।

आंवला जूस : आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इस जूस को पीने से इम्युनिटी मजबूत होता है, साथ ही ये पाचन सुधारता है। ये जूस त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद अगर इस रोज सुबह खाली पेट पीना ज्यादा लाभकारी होता है।

गाजर-चुकंदर जूस : यह जूस शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। ये जूस खून साफ करता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाता है साथ ही ऊर्जा देता है। इसमें थोड़ा नींबू मिलाने से इसका असर और बढ़ जाता है।

संतरा जूस : संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है। इस जूस को पीने से सर्दी-जुकाम से बचाव होता है साथ ही इम्युन सिस्टम मजबूत और शरीर को हाइड्रेट रखता है। लेकिन आप ये जरूर कोशिश करें की ताजा जूस ही पिएं, पैकेज्ड से बचें।

हल्दी-अदरक जूस : यह एक नेचुरल एंटीबायोटिक ड्रिंक है। यह सूजन कम करता है, इंफेक्शन से लड़ता है, गले की खराश में राहत देता है इसमें शहद मिलाकर पीना और फायदेमंद होता है।

अनारजूस : अनार एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये जूस दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है। ये खून बढ़ाने में मददगार और कमजोरी दूर करता है। रोज एक गिलास अनार जूस से शरीर मजबूत रहता है।

'यह परिशिष्ट किसी एक मत या संप्रदाय का प्रचार नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सहअस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों का मंच है।'

'आध्यात्मिक संवाद'

कान्हा के इन नौ धामों में बसती है दिव्यता

महाभारत और पुराणों में भगवान श्रीकृष्ण का जीवनकाल 125 साल का बताया गया है। लेकिन अपने जीवनकाल में शायद ही श्रीकृष्ण लंबे समय तक एक स्थान पर रहे हों। भगवान श्रीकृष्ण का जीवन अलग-अलग चरणों में बीता। खतरे के माहौल को देखते हुए बचपन छिपकर बिताया। यौवन काल प्रेम और विरह से भरा, वयस्क जीवन जिम्मेदारियों से भरा और आखिर में वैराग्य और एकांत से जुड़ी यादें। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको जन्म से लेकर वैराग्य तक भगवान श्रीकृष्ण के 9 पवित्र धाम के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर आज भी दिव्यता गूंजती है।

मथुरा

>> भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था।
>> यहां पर भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मंदिर और विश्राम घाट है।
>> उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि है।

गोकुल

>> जन्म के बाद श्रीकृष्ण का पालन-पोषण नंद बाबा के घर गोकुल में ही हुआ था।
>> यहां के मुख्य स्थल नंद भवन और रमणरेती है।
>> आज भी यहां की गलियां बाल कृष्ण की लीलाओं की गवाही देती है।
>> यहां पर आज भी मां यशोदा की लोरियां और घर-घर में श्रीकृष्ण के माखन चुराने की कथाएं प्रचलित हैं।

वृंदावन

>> वृंदावन श्रीराधा-कृष्ण की रासलीलाओं का पावन स्थल है।
>> वृंदावन के प्रमुख मंदिर प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर है।
>> यहां का हर कोना प्रेम और भक्ति से सराबोर रहता है।
>> यहां पर रात के समय राधा रानी और गोपियों की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है।

नंदगांव

>> नंदगांव भगवान श्रीकृष्ण के किशोर काल से जुड़ा है।
>> यहां का मुख्य आकर्षण नंद राय मंदिर है।

बरसाना

>> यह गांव राधा जी का गांव माना जाता है।
>> यहां पर लाडली जी का मंदिर है। वहीं बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है।

उज्जैन

>> उज्जैन में श्रीकृष्ण ने गुरु संदीपनि के आश्रम में शिक्षा ली थी।
>> यहां पर आज भी संदीपनि ऋषि का आज भी दर्शनीय है।
>> यहां पर श्रीकृष्ण की सुदामा से मित्रता हुई थी।

द्वारका

>> मथुरा छोड़कर भगवान श्रीकृष्ण ने द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था।
>> यहां का मुख्य आकर्षण द्वारकाधीश मंदिर है।
>> द्वारकाधीश मंदिर चार धामों में से एक प्रमुख धाम है।

कुरुक्षेत्र

>> महाभारत युद्ध के दौरान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था।
>> यहां का विशेष स्थल ज्योतिसर है।
>> यह स्थान कर्म और धर्म का प्रतीक है।

सोमनाथ

>> माना जाता है कि श्रीकृष्ण ने यहीं प्रभास क्षेत्र में देह त्याग किया था।
>> सोमनाथ मंदिर के पास स्थित यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है।

क्या है स्वर्ग और वैकुंठ में अंतर?

जानें हिंदू धर्म के अनुसार इनका महत्व

हिंदू दर्शन में मृत्यु के बाद अक्सर स्वर्ग, नरक और वैकुंठ के बारे में बात की जाती है। ऐसा माना जाता है कि, मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से इनमें से किसी एक लोक में पहुंचती है। जहां अधिकांश लोग स्वर्ग और नरक के बीच अंतर को साफ तौर पर समझते हैं, वहीं स्वर्ग और वैकुंठ को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति में रहते हैं। यद्यपि दोनों को ही स्वर्ग माना जाता है, फिर वे एक समान नहीं है। आइए समझते हैं कि स्वर्ग और वैकुंठ प्रकृति, उद्देश्य और आध्यात्मिक स्थिति में किस तरह से अलग हैं?

स्वर्ग और वैकुंठ के बीच का अंतर : सनातन धर्म के अनुसार, स्वर्ग एक अस्थायी लोक है, जहां पुण्य आत्माएं अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने जाती हैं। इन सुखों का अनुभव करने के बाद आत्मा को अपने कर्मों का चक्र जारी रखने के लिए पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। दूसरी ओर, वैकुंठ भगवान विष्णु का शाश्वत निवास स्थान है। एक दिव्य आध्यात्मिक लोक जो भौतिक अस्तित्व से परे है। जो लोग वैकुंठ पहुंचते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे जन्म-मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं।

वैकुंठ पहुंचने के बाद क्या होता है? : शास्त्रों में वैकुंठ धाम को शाश्वत आनंद और दिव्य प्रकाश का स्थान बताया गया है, जहां न तो दुख है और न ही आसक्ति। यह स्वर्ग लोक से परे स्थित है, और उससे भी ऊपर भगवान शिव का निज निवास स्थान कैलाश धाम है। वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी, देवी श्री और देवी भू देवी भी निवास करती हैं और असंख्य दिव्य सेवकों से घिर रहते हैं। कहा जाता है कि, यह लोक हजारों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशमान है और शांति, भक्ति और शाश्वत आनंद से भरा है। जो लोग यहां पहुंचते हैं वे जन्म-मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं।

पेज-1 का शेष

पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिले विजय...

उस वक्त यह खबरें थीं कि वह राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मुलाकात करेंगे, लेकिन तब ऐसा संभव नहीं हो पाया था। तब से लेकर अब तक कांग्रेस और टीवीके के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। ऐसे में अब सीएम विजय राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने आए हैं।

संसदीय समिति के सामने सरकार का वादा-'अब नहीं होगी कोई चूक'...

वैश्विक स्तर से सीख और समन्वय की जरूरत संसदीय समिति के सदस्यों ने अधिकारियों को अमेरिका और चीन जैसे देशों का उदाहरण दिया, जहां इतनी बड़ी परीक्षाएं बिना किसी शिकायत या पेपर लीक के आयोजित की जाती हैं। समिति ने सुझाव दिया कि भारत को भी इन वैश्विक मानकों और 'बेस्ट प्रैक्टिसेज' को अपनाना चाहिए। इसके साथ ही, भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए एनएमसी और एनटीए के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया गया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आगामी परीक्षा के लिए 'फूल-प्रूफ' बंदोबस्त किए जा चुके हैं। छात्रों का तनाव और आत्महत्याओं पर चिंता बैठक में सांसदों ने पेपर लीक और परीक्षाओं के रद होने से छात्रों में बढ़ते मानसिक तनाव और आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की।

नौसेना को मिलेंगे 449 करोड़ के एडवांस ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम जैमर्स...

आमतौर पर यह डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल भेजता है, जिन पर मोबाइल कॉल, वाई-फाई, जीपीएस और अन्य वायरलेस सेवाएं काम करती हैं। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल जरूरी होता है लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां इस तरह के सिस्टम को एक्टिव करना बैन माना जाता है। जब जैमर को एक्टिव किया जाता है तो असली नेटवर्क सिग्नल कमजोर हो जाता है। कई बार ऐसे इलाकों में फोन कॉल कटने लगते हैं, इंटरनेट भी बेहद धीमा पड़ जाता है और कई बार तो इंटरनेट बंद ही हो जाता है। इतना ही नहीं जैमर का असर नेविगेशन पर भी पड़ता है। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु की कंपनी ASSPL के साथ समझौता किया है, जो कि भारतीय समुद्री जहाजों को सुरक्षित रखने में कारगर साबित होगा।

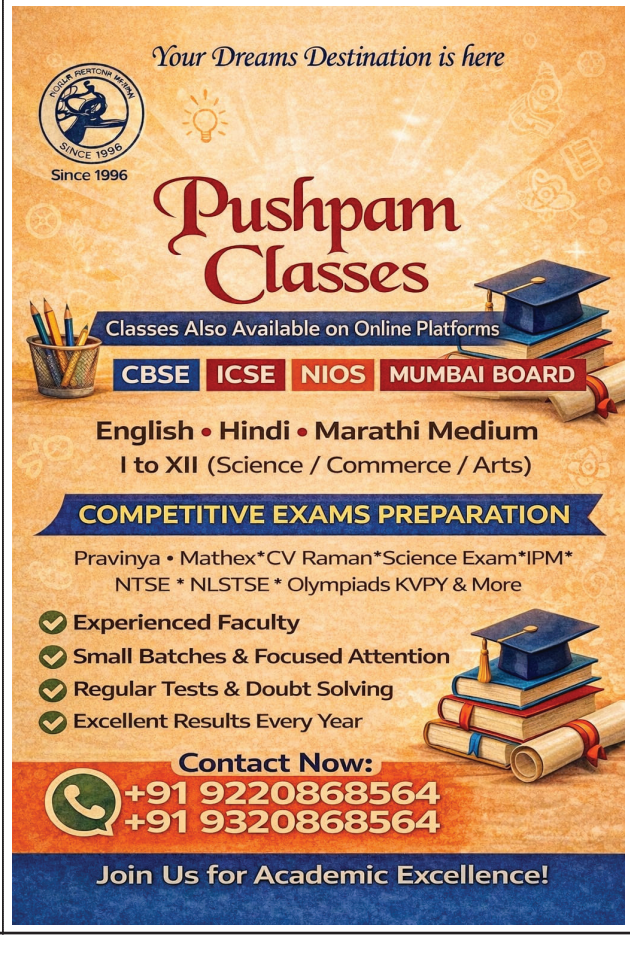

कालस्य परिवर्तनम् तथा भारतस्य नूतनं व्याकरणम्

राजनीतिसमीकरणेभ्यः कृषिक्षेत्रस्य प्रयोगशालां यावत् अन्तरिक्षस्य पाठशालां च-एते अस्मान् किं शिक्षयन्ति?

"पञ्चाङ्गस्य पत्रं परिवर्तयितुं सुलभम्, किन्तु युगस्य पृष्ठं परिवर्तयितुं दुष्करम्। अद्य भारतम् तादृशस्य परिवर्तनस्य सङ्क्रमणकाले स्थितम् अस्ति।"

अद्य भारते राजनीतिक्षेत्रे, कृषिक्षेत्रे तथा विज्ञानक्षेत्रे महत्त्वपूर्णाः परिवर्तनप्रवाहाः दृश्यन्ते। यद्यपि एते विषयाः पृथक प्रतीयन्ते, तथापि तेषां मूलभावः एक एव अस्ति-सहकारः, सन्तुलनम् तथा दूरदर्शिता।

राजनीतिक्षेत्रे २०२४ तमे वर्षे सम्पन्नानि निर्वाचनानि अस्मान् बोधयन्ति यत् जनतान्त्रिकव्यवस्थायां केवलं बहुमतमेव निर्णायकं न भवति। बहुषु निर्वाचनक्षेत्रेषु विजयपराजययोः अन्तरं न्यूनम् आसीत्। अतः विभिन्नदलानां समन्वयः तथा गठबन्धनभावना अधिकं महत्त्वं प्राप्नोति। एतादृशे सन्दर्भे आसनविभाजनं न दुर्बलतायाः प्रतीकः, अपितु दूरदर्शिनः नेतृत्वस्य तथा सामूहिकहितचिन्तनस्य परिचायकः अस्ति। संवादः सहकारश्च जनतन्त्रस्य प्राणतत्त्वम् अस्ति।

कृषिक्षेत्रे मानवरहितविमानानि, संवेदकयन्त्राणि तथा उन्नतबीजानि नूतनपरिवर्तनस्य वाहकानि जातानि। एतैः उत्पादनवृद्धिः सम्भवति, किन्तु तेषां विवेकपूर्णः उपयोगः अधिकमहत्त्वपूर्णः अस्ति। कृषकसङ्कटनानि कृषकानां सामूहिकशक्तिं संवर्धयन्ति तथा तेषां हितसंरक्षणे महत्त्वपूर्णा भूमिकां निर्वहन्ति। विज्ञानक्षेत्रे अपि द्वौ महत्त्वपूर्णौ सन्देशौ प्राप्येते। एकतः समुद्रतापवृद्धिः तथा प्रबलचक्रवाताः जलवायुपरिवर्तनस्य गाम्भीर्यम् उद्घोषयन्ति। अपरतः दूरस्थादन्तरिक्षादागच्छन्तः रहस्यमयाः सङ्केताः ब्रह्माण्डस्य अद्याप्यनावृतान् रहस्यान् प्रकाशयन्ति। भारतीयवैज्ञानिकसंस्थाः अस्मिन् क्षेत्रे गौरवपूर्णं योगदानं प्रददति।

अन्ते वक्तुं शक्यते यत् राजनीति सहकारस्य महत्त्वं शिक्षयति, कृषि सङ्गठनस्य शक्तिं दर्शयति, विज्ञानं च जिज्ञासायाः गौरवं प्रकाशयति। अतः नूतनं भारतम् केवलं कल्पना नास्ति, अपितु सहकारस्य, सजागतायाः तथा दृढसंकल्पस्य नूतनं व्याकरणम् अस्ति।

क्षणमात्रस्य प्रमादः, कोटिधनस्य हानिः

किं भारतस्य विद्युत्प्रणाली अर्धचालक-क्रान्तेः दृढमूलाधारः भवितुमर्हति?

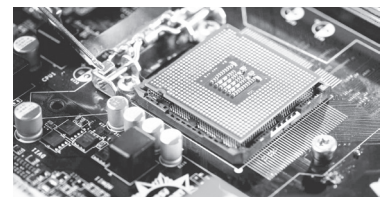

अर्धचालक-चिप (Semiconductor Chip) आधुनिक-प्रौद्योगिकीयुगस्य मेरुदण्डः अस्ति। दूरभाषयन्त्रेभ्यः संगणकपर्यन्तं, कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः प्रणालिभ्यः रक्षाक्षेत्रपर्यन्तं, सर्वे क्षेत्राः अस्यां प्रौद्योगिक्यां निर्भरन्ति। किन्तु चिप-निमार्ण केवलं प्रौद्योगिक्याः निवेशस्य च विषयः नास्ति, अपितु उच्चगुणवत्तायुक्तायाः स्थिरविद्युत्पूर्तेः अपि प्रश्नः अस्ति। चिप-निर्माणप्रक्रिया अत्यन्तं सूक्ष्मा संवेदनशीला च भवति। विद्युत्प्रवाहे क्षणिकः व्यवधानः, अथवा विभवभेदे लघुतमः अपि विकारः, कोटिशः मूल्यवन्तः सिलिकॉन-पट्टकान् (Sillicon Wafers) अनुपयोगिनः कर्तुं शक्नोति। भारतदेशस्य पर्याप्ता विद्युतुत्पादनक्षमता अस्ति, तथापि अनेकासु प्रदेशेषु विद्युत्गुणवत्ता तथा वितरणव्यवस्था औद्योगिकापेक्षाः सम्पूर्णतया पूरयितुं न शक्नोति। अपरा चुनौती हरितऊर्जायाः क्षेत्रे दृश्यते। सौर-ऊर्जा तथा वाय्वीय-ऊर्जा पर्यावरणहितकरौ स्तः, किन्तु तयोः उपलब्धता सर्वदा समानरूपेण न भवति। परन्तु चिप-निर्माणकेन्द्राणि अहोरात्रं निरवच्छिन्नां विद्युत्पूर्तिम् अपेक्षन्ते। एतदतिरिक्तं चिप्-निमार्णे अत्यन्तशुद्धस्य जलस्य आवश्यकता भवति, यस्य शोधनाय पुनर्चक्रणाय च पर्याप्ता विद्युत्शक्तिः व्ययते। यदि भारतः वैश्विक-अर्धचालक-उद्योगस्य प्रमुखकेन्द्रं भवितुमिच्छति, तर्हि धोलेरा-नोएडा-प्रभृतिषु औद्योगिकक्षेत्रेषु विशेषविद्युत्ाधारसंरचनानां विकासः आवश्यकः।

नाटकम् : मायेयं वा ब्रह्म वा? भृगोः सत्ययात्रा

(तैत्तिरीयोपनिषदः भृगुवल्ल्याः आधारेण)

पात्राणि-सूत्रधारः, भृगुः, वरुणः, माया, अन्ना, प्राणा, मना, विज्ञाना

Dr. Vandana Mishra
M. A. NET (JRF) PHD

प्रस्तावना

सूत्रधारः : "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति।" यतः सर्वं जगदुत्पद्यते, येन च धार्यते, यस्मिन् च अन्ते लीयते, तदेव ब्रह्म। तस्यैव अन्वेषणस्य कथा इयं-भृगोः सत्ययात्रा।

प्रथमः दृश्यः-जिज्ञासाया उदयः

(तपोवने भृगुः चिन्तामग्नः उपविष्टः।)

माया : भो भृगो! किमर्थं चिन्तया क्लिश्यसे? यद्दृश्यते तदेव सत्यम्। खाद, पिब, रमस्व।

भृगुः : न माये! मम अन्तःकरणे प्रश्नो जायते। कुतः अयं लोकः? किं तस्य मूलम्?

(वरुणः प्रविशति।)

भृगुः : भगवन् पितः! 'अधीहि भगवो ब्रह्मेति।' ब्रह्मणः स्वरूपं बोधयतु।

वरुणः : वत्स! यतः भूतानि जायन्ते, येन जीवन्ति, यस्मिन् लीयन्ते च, तदेव ब्रह्म। किन्तु न केवलं श्रवणेन तत् ज्ञायते। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व।

भृगुः : यथाज्ञापयति भवान्।

द्वितीयः दृश्यः-अन्नमयस्य मोहः

(अन्ना धान्यपूर्णपात्रं धारयन्ती आगच्छति।)

अन्ना : अहम् अन्नम्। मत्तः शरीराणि भवन्ति। मया विना जीवनं न सम्भवति।

भृगुः : 'अन्नं ब्रह्मेति व्यजानाम्।' अन्नस्य महत्त्वं महान्।

मायाः साधु! अन्वेषणं समाप्तम्। अन्नमेव ब्रह्म।

भृगुः: न। अन्नं जडम् अस्ति। तस्य भोक्ता कः?

(वरुणस्य समीपं गच्छति।)

भृगुः : भगवन्! अन्नं महत्, किन्तु ब्रह्म न भवति।

वरुणः : समीचीनं चिन्तितम्। पुनस्तपस्व।

तृतीयः दृश्यः-प्राणस्य आकर्षणम्

प्राणा : अहं प्राणः। मया विना देहः केवलं मृत्तिका।

भृगुः : 'प्राणो ब्रह्मेति व्यजानाम्।'

माया : एवमेव! शक्तिः, सामर्थ्यं, सिद्धयः — सर्वं प्राणे एव।

भृगुः : किन्तु प्राणोऽपि चलति, निवर्तते च। तं प्रेरयति कः?

(वरुणस्य समीपे।)

वरुणः : यावत् प्रश्नः तिष्ठति, तावत् अन्वेषणमपि तिष्ठति।

भृगुः : पुनः तपः करिष्यामि।

चतुर्थः दृश्यः-मनसः मायाजालम्

मना : अहं मनः। संकल्पाः, स्वप्नाः, प्रेम, भावनाश्च मत्त एव।

माया : पश्य! गीतम्, काव्यम्, सौन्दर्यम्-एष एव जीवनस्य सारः।

भृगुः : मनः अद्भुतम्, किन्तु चञ्चलम्। कदाचित् हृष्टम्, कदाचित् विषण्णम्। यत् परिवर्तते, तत् कथं नित्यम्?

(वरुणस्य समीपं गच्छति।)

वरुणः : मनसः अपि साक्षिणं पश्य।

भृगुः : तमेव अन्वेषयामि।

पञ्चमः दृश्यः-विज्ञानस्य गौरवम्

विज्ञाना : अहं बुद्धिः। विवेकः मम स्वरूपम्।

माया : भृगो! त्वं ज्ञानी अभवः। यशः, सम्मानः, कीर्तिः-सर्वं तव।

भृगुः: ज्ञानं श्रेष्ठम्। किन्तु 'अहं ज्ञानी' इति अहंकारः बन्धनमेव। बुद्धेः प्रकाशकः कः?

(वरुणस्य समीपे।)

वरुणः : वत्स! अन्तिमं तपः कुरु।

माया : अग्रे किमपि नास्ति!

वरुणः : यः मध्ये एव तिष्ठति, स लक्ष्यं न प्राप्नोति।

षष्ठः दृश्यः-आनन्दस्य साक्षात्कारः

(मञ्चे मन्दप्रकाशः। भृगुः ध्यानस्थः। माया विकरालरूपेण आगच्छति।)

माया : अन्नं त्यक्तम्, प्राणः त्यक्तः, मनः त्यक्तम्, बुद्धिरपि त्यक्ता। अधुना किं शेषम्?

भृगुः : नाहमन्नम्। न प्राणः। न मनः। न बुद्धिः। यः एतेषां सर्वेषां साक्षी, स एव सत्यः।

माया : अहमेव संसारः!

भृगुः : त्वं दृश्यरूपा। अहं तु द्रष्टा।

(स्वर्णप्रकाशः सर्वत्र प्रसृतः।)

भृगुः : 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानाम्!' आनन्दादेव भूतानि जायन्ते। आनन्देन जीवन्ति। आनन्दे एव लीयन्ते।

(माया शनैः अदृश्यते।)

वरुणः : साधु वत्स! एषा एव भार्गवी-वारुणी विद्या। त्वया माया न हता, अपि तु ज्ञाता।

अन्ना, प्राणा, मना, विज्ञाना (एकस्वरेण) : वयं सोपानानि आस्म। लक्ष्यं तु आनन्दः आसीत्।

वरुणः : अन्नं, प्राणः, मनः, बुद्धिः — एतानि साधनानि। यः नित्यः, शुद्धः, आनन्दस्वरूपः, स एव ब्रह्म।

सूत्रधारः : भृगोः एषा यात्रा केवलं तस्य नास्ति। सा अस्माकं सर्वेषाम् अन्तर्मार्गयात्रा अस्ति। यः स्वान्ते सत्यं पश्यति, स एव ब्रह्मणः साक्षात्कारं प्राप्नोति।

सर्वे एकस्वरेण : 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व।' ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

(पर्दः पतति।)

विशेष विश्लेषणम् जूनमासः २०२६

परिवर्तमानं भारतम् : राजनीतिः, शिक्षा च अर्थव्यवस्था च नूतनां दिशं सूचयन्ति

जूनमासस्य प्रथमसप्ताहः भारतस्य राजनैतिके, शैक्षिके, आर्थिके च क्षेत्रे बहूनां महत्त्वपूर्णानां घटनानां साक्षी अभवत्। केचन समाचाराः आधिकारिकरूपेण प्रमाणिताः सन्ति, अन्येषां विषये तु अद्यापि विस्तृतस्पष्टीकरणस्य अपेक्षा वर्तते। तथापि एते घटनाक्रमाः राष्ट्रस्य नीतिषु, लोकतान्त्रिकव्यवस्थायां विकासमार्गे च नूतनां चर्चां जनितवन्तः।

राजनीतिक्षेत्रम् : विपक्षैक्यस्य परीक्षा

राष्ट्रीय राजनीतौ INDIA नामक विपक्षगठबन्धनस्य क्रियाकलापाः विशेषचचार्याः केन्द्रबिन्दवः अभवन्। विभिन्नदलानां मध्ये रणनीतिसमन्वयविषये मतभेदाः प्रकाशमागताः। कतिपयदलैः कांग्रेसदलस्य कार्यपद्धत्यां प्रश्नाः उत्थापिताः, अन्यैः संवादस्य नियमितसभानां च आवश्यकता प्रतिपादिता।

राजनीतिविश्लेषकानां मतम् अस्ति यत् आगामिनिषु निर्वाचनेषु विपक्षस्य सफलतायै सुदृढसङ्गठनं, परस्परसामञ्जस्यं, स्पष्टकार्यक्रमश्च अत्यावश्यकाः भविष्यन्ति।

अस्मिन्नेव काले प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदिनः दीर्घकालपर्यन्तं निर्वाचितप्रधानमन्त्रित्वस्य नूतनकीर्तिमानस्य चर्चा राष्ट्रव्यापिनी अभवत्। एषा उपलब्धिः भारतीयलोकतन्त्रस्य इतिहासे महत्त्वपूर्णः अध्यायः मन्यते।

शिक्षाक्षेत्रम् : पारदर्शितायाः विश्वसनीयतायाश्च आवश्यकता

शिक्षाक्षेत्रे NEET-UG परीक्षासम्बद्धाः विषयाः जनमानसस्य आकर्षणकेन्द्रे स्थिताः। परीक्षाव्यवस्थायाः विश्वसनीयता, प्रश्नपत्रस्य सुरक्षा, व्यवस्थापनप्रक्रियायाश्च विषये व्यापकविमर्शः अभवत्।

राष्ट्रीयपरीक्षाअभिकरणेन (NTA) सुरक्षा-व्यवस्थायाः सुदृढीकरणाय तथा परीक्षाप्रक्रियायाः अधिकपारदर्शितायै विविधाः उपायाः स्वीकृताः इति ज्ञायते।

विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् केवलं प्रौद्योगिकसुधाराः पर्याप्ताः न भवन्ति; उत्तरदायित्वम्, पारदर्शिता, संस्थासु जनविश्वासश्च समानरूपेण आवश्यकाः सन्ति। लक्षशः विद्यार्थिनां कृते एषा परीक्षा केवलं स्पर्धा नास्ति, अपितु तेषां भविष्यनिर्माणस्य आधारशिला अस्ति।

अर्थव्यवस्था : वैश्विकसहकार्यस्य नूतनावकाशाः

आर्थिकक्षेत्रे भारत-अमेरिका-व्यापारवार्ताः सकारात्मकसंकेताः प्रदत्तवन्त्यः। व्यापारः, निवेशः, विपणिप्रवेशः इत्यादिविषयेषु द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये सार्थकः संवादः प्रवर्तमानः अस्ति।

यदि प्रस्तावविताः सन्धयः अन्तिमरूपं प्राप्स्यन्ति, तर्हि भारतीयनिर्यातस्य, विनिर्माणक्षेत्रस्य, रोजगारावकाशानां च विस्तारः सम्भाव्यते।

तदनन्तरं भारतः अन्यैः प्रमुखवैश्विकसहयोगिभिः सह अपि आर्थिकसम्बन्धान् दृढीकर्तुं प्रयत्नशीलः अस्ति। विशेषज्ञानां मतानुसारं वैश्विकानिश्चितायाः मध्ये अपि भारतस्य विकासगतिः, निवेशाकर्षणक्षमता च तस्य प्रमुखशक्तिरूपेण उदेति।

वैश्विकपरिदृश्यम्

पश्चिमएशियाक्षेत्रे वर्धमानः तनावः, ऊर्जाविपण्यां अस्थिरता, भू-राजनैतिकपरिवर्तनानि च भारतस्य सम्मुखे नूतनचुनौतयः स्थापयन्ति। एतादृशे काले सन्तुलिता कूटनीतिः, ऊर्जासुरक्षा, आर्थिकस्थैर्यं च राष्ट्रस्य प्रमुखप्राथमिकतासु गणितानि सन्ति।

भारतवर्षम् अधुना परिवर्तनस्य महत्त्वपूर्णे चरणे स्थितम् अस्ति। राजनीतौ नूतनसमीकरणानि निर्मीयन्ते, शिक्षाक्षेत्रे पारदर्शितायाः विश्वसनीयतायाश्च अपेक्षा वर्धते, अर्थव्यवस्था च वैश्विकमञ्चे स्वस्थानं दृढीकर्तुं प्रयतते।

अद्य घटमानाः एते घटनाक्रमाः केवलं वर्तमानकालस्य दर्पणाः न सन्ति, अपितु भविष्यस्य दिशानिर्देशकाः अपि सन्ति। अतः एते घटनाक्रमाः केवलं द्रष्टव्याः न, अपितु तेषां दीर्घकालीनप्रभावाः अपि सूक्ष्मतया अवगन्तव्याः

Thinking is the biggest challenge in river linking projects, not money : Vice President

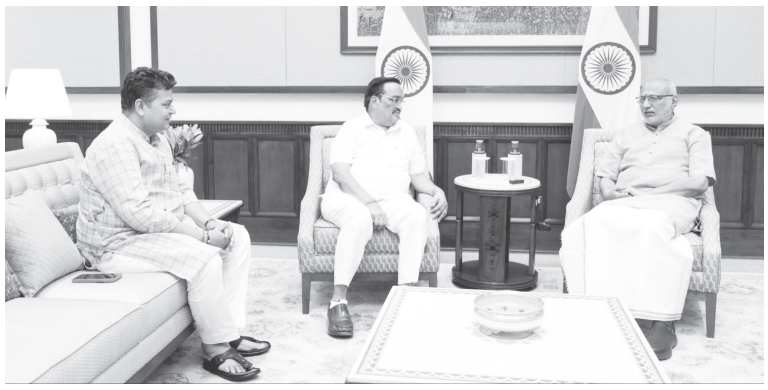

New Delhi: Vice President C.P. Radhakrishnan said that river linking projects should be progressed rapidly to ensure water security in the country. He clarified that lack of funds is not the biggest hurdle in these projects, but people's thinking and political reasons are the biggest challenge. “Lack of funds is not the big problem in implementing river interlinking projects, but lack of thinking and political will is more challenging,” Radhakrishnan said during a meeting with Jal Shakti Ministry officials at Upa Rashtrapati Bhavan. The Vice President said that interlinking of rivers will reduce water crisis, help tackle drought, increase irrigation area and enable balanced development in different parts of the country. Vice President C.P. Radhakrishnan suggested creating documentaries and permanent records on important projects like Ken-Betwa, so that future generations can be proud of these nation building works. He reminded that earlier too he had undertaken a padyatra in support of the interlinking of rivers campaign.

In the meeting, Union Jal Shakti Minister C.R. Patil and Minister of State Raj Bhushan Choudhary were also present. Both also invited the Vice President to participate in the ‘India International Water Week’ to be held in September 2026. This meeting is being considered an important step towards giving national priority to water conservation, river interlinking projects and groundwater augmentation.

Main points

>> Emphasizing the need for a visionary and collaborative approach for better management of water in the national interest.

>> Appreciated the ‘Jal Sanchay Jan Bhagidari’ campaign. More than 1.55 crore water conservation structures have been built or registered in the second phase of the campaign, far exceeding the target.

>> Reviewed the progress of major river interlinking projects like Ken-Betwa Link, Parvati-Kalisindh-Chambal Link and Godavari-Kaveri Link.

The 79A Labyrinth

Redevelopment Policy and the Growing Trust Deficit in Mumbai’s Housing Sector

Sudhir Salunke/ Lalbaug

Mumbai: Section 79A of the MHADA Act was enacted with a clear objective: to ensure the timely redevelopment of old and dilapidated cessed buildings. Under the provision, if landlords or tenant cooperative societies fail to initiate redevelopment within the prescribed period, MHADA is empowered to intervene and take the process forward. Yet, its implementation has raised important concerns.

First, if MHADA itself acknowledges limitations in financial resources, how can it realistically undertake large-scale redevelopment after assuming control of properties? Second, judicial observations in recent cases have questioned the manner in which certain notices were issued, highlighting the need for greater procedural transparency and administrative accountability. Third, many projects remain stalled despite the consent of a majority of residents, forcing thousands of families to continue living in unsafe and deteriorating structures.

The original intent of Section 79A was to protect public interest and prevent redevelopment from being held hostage to delay, indecision, or vested interests. What citizens require today is a transparent, accountable, and time-bound framework that safeguards both the purpose of the law and public confidence in its execution.

The law provides the tool, but it is the intent of implementation that determines whether that tool builds homes or breaks trust.

India's Major Abhilasha Barak gets award in UN

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi congratulated Major Abhilasha Barak of Haryana on receiving the UN Military Gender Advocate of the Year Award. The PM said that this honor is a recognition of his excellent service and India's long-standing contribution to the peace-keeping efforts of the United Nations. Barak is currently working with the United Nations Mission in Lebanon. She has been given this award for her efforts to connect with and work for women and girls during her deployment in the West Asian country. She is also the first woman combat helicopter pilot of the Indian Army. The Prime Minister said that Major Barak is working as the Engagement Team Commander and Gender Focal Point in the United Nations Interim Force in Lebanon.

The PM said, 'This honor is a recognition of his outstanding service and India's long-standing contribution to the peace-keeping efforts of the United Nations.

SBI handed over dividend of Rs 8,813 crore to the central government

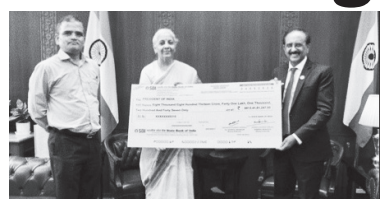

New Delhi: State Bank of India (SBI), the country's largest public sector bank, has handed over a dividend check of Rs 8,813 crore to the central government for the financial year 2025-26. This check is from SBI Chairman C.S. Shetty handed over to Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman. Finance Minister's Office (FMO), while sharing information on social media platform X, said that Finance Minister Nirmala Sitharaman has met SBI Chairman C.S. A dividend check of Rs 8,813 crore has been received from Shetty for the financial year 2025-26. This dividend payment reflects the strong financial performance of SBI. Moreover, it is also being seen as a significant contribution to the non-tax income of the Central Government. As a public sector bank, SBI plays an important role in the banking system of the country and its contribution will also strengthen the government revenue. At an industry event held in Mumbai earlier this month, C.S. Shetty had supported the decision of the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India to keep interest rates stable. He had said that keeping rates stable in the current circumstances will be helpful in maintaining financial stability and accelerating economic growth. He had said that the inflation situation is important for policy makers, but at present maintaining stability in interest rates is an appropriate step for balanced economic growth. The SBI chairman had appealed to investors to look beyond short-term fluctuations in the stock market.

From metro to bullet train... central government made master plan of rail project for Bengal

Kolkata: A key approval for 61 railway projects is expected to reshape the railway network in West Bengal, an eastern state that serves as a crucial gateway to the northeast. Railway Minister Ashwini Vaishnaw on Friday held a key meeting with Chief Minister Suvendu Adhikari at the state secretariat.

Sources indicate that various railway projects were discussed during the meeting. Vaishnaw and Adhikari subsequently held a press conference, during which the railway minister announced 538 new flyovers and underpasses in Bengal. He said that 102 'Amrit Bharat' stations will also be developed in West Bengal in the days to come. Besides, Kolkata Metro will get 60 new rakes within five years. The much-awaited bullet train service will also be launched between Siliguri and Delhi. "This bullet train

will start from New Delhi and will reach Siliguri in North Bengal via Lucknow, Varanasi, and Patna. The distance will be covered in just six hours. Apart from that, 60 new train services will be introduced in the state in the next five years," the railway minister added. A dedicated east-west freight corridor has also been announced to connect Dankuni in Bengal with Surat in Gujarat. Projects worth Rs 1 lakh crore will be undertaken for Bengal, the railway minister said, stating that the funds are ready. Vaishnaw said the previous Trinamool government went to the High Court and the Supreme Court to stall railway projects to deprive the people of Bengal of development. "However, you will now be able to work freely and wholeheartedly. The previous government did not allow you to work," the minister told reporters at Nabanna. Echoing him, Chief Minister Suvendu Adhikari said that during the Trinamool regime, centre-state relations had virtually turned into a state of conflict and caused many projects to stall. "But the people of West Bengal will now fully reap the benefits of a 'double-engine' government. Approval has already been granted for 61 railway projects," he said. The chief minister has also directed the district magistrates to cooperate with the Railway Board for railway network expansion and easing of the land acquisition process.

250 MW solar power project to be built on defense land in Sitapur : Rajnath Singh

The project will be developed on 850 acres of defense land

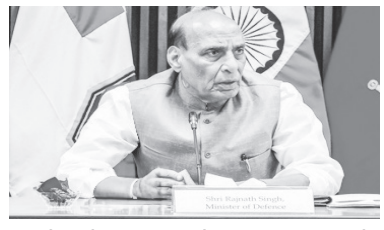

Lucknow: Defense Minister Rajnath Singh has approved setting up a 250 MW capacity solar power project on the vacant land of the Defense Ministry in Sitapur, Uttar Pradesh. The project consisting of Battery Energy Storage System (BESS) will be the first renewable energy project of its kind to be developed on defense land and will set a new benchmark for future solar and energy storage projects. According to the Defense Ministry, the project will be set up on approximately 850 acres of vacant defense land located in the former cantonment area of Sitapur. It will also include battery energy storage systems integrated with large-scale solar power generation, making energy supplies more reliable and efficient. This initiative is considered an important step towards enhancing energy security, promoting clean energy and maximum utilization of unused land of the Ministry of Defence. The objective of the project is to meet the energy needs of defense establishments located across the state and strengthen their energy security. Along with this, dependence on traditional grid based electricity will be reduced, which is expected to reduce the expenditure on power purchase significantly in the long run. The Defense Ministry believes that this will reduce the burden of electricity expenditure on the government treasury and will provide stable and affordable energy to defense establishments. After completion of the project, Sitapur Solar Power Project will be one of the most important renewable energy projects in the country established on defense land.

Lord Shri Krishna says, don't think so much about life, I have given you this life, you must have thought about you...!!

PUPILS TIMES

"Whatever happened, happened for good; whatever is happening, is happening for good; whatever will happen, will also be good."
Geeta Sermon

Friday, 12 June to 18 June 2026

Gallantry Awards 2026

President Murmu honored 51 brave soldiers

New Delhi: President Draupadi Murmu presented gallantry awards at the Defense Investiture Ceremony-I held at Rashtrapati Bhavan. The ceremony began with the singing of the national song and anthem. Prime Minister Narendra Modi and Defense Minister Rajnath Singh were also present at the ceremony, where gallantry and distinguished service awards were presented to armed forces personnel.

During this period, a total of 51 personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State/Union Territory Police were honored with gallantry awards. These awards include 7 Kirti Chakras, 15 Vir Chakras and 29 Shaurya Chakras. The award was given to the awarded soldiers and officers for extraordinary courage, indomitable gallantry and service to the nation without sacrificing their lives in the line of duty.

Group Captain Ranjit Singh Sidhu also honored with Vir Chakra

Lieutenant Colonel Sushil Bisht, Wing Commander (now Group Captain) Joy Chandra, Group Captain Manish Arora and Group Captain Ranjit Singh Sidhu were awarded the Vir Chakra for extraordinary gallantry, courage and distinguished service. Rifleman Dhruba Jyoti Dutta and Naik Rahul Singh were awarded the Shaurya Chakra for their extraordinary bravery, courage and devotion to duty. Additionally, Major Shivant Yadav and Lieutenant Colonel Nitish Bharat Shukla were awarded the Shaurya Chakra in recognition of their extraordinary courage, unwavering devotion to duty and distinguished service to the country.

Lieutenant Colonel got Shaurya Chakra for killing terrorists

Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla of the 19th Battalion of the Sikh Regiment of the Indian Army was awarded the Shaurya Chakra for displaying extraordinary bravery and gallantry in killing three terrorists along the LoC. Naib Subedar Satish Kumar was awarded the Vir Chakra for his extraordinary gallantry, unwavering courage and distinguished service in the line of duty.

Major Aditya Pratap Singh honored with Shaurya Chakra

Major Aditya Pratap Singh of the Indian Army was awarded the Shaurya Chakra for displaying extraordinary gallantry during a military operation in the border area of Arunachal Pradesh. Inspector Laxman Kevat and Inspector Rameshwar Prasad Deshmukh of Chhattisgarh Police were awarded the Shaurya Chakra for displaying extraordinary bravery during an anti-Naxal operation in Chhattisgarh.

Flight Lieutenant Arshveer Singh honored with Vir Chakra

President Draupadi Murmu awarded the Vir Chakra to Flight Lieutenant (current Squadron Leader) Arshveer Singh Thakur for extraordinary gallantry, courage and distinguished service during operational duty. Lieutenant Commander Dilna K. And Rupa A. Was awarded the Shaurya Chakra for exceptional courage, seamanship and stamina during Operation Sagar Parikrama II.

India deployed 12 ready to fire nuclear weapons for the first time

New Delhi: In a major change in nuclear weapons policy, India has deployed 12 nuclear warheads for the first time. This information has come out in the recent report of Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). SIPRI, the world's leading weapons-tracking organization, has said in its latest report that India has deployed 12 nuclear weapons for the first time. This is a major change from the decades-long policy under which nuclear weapons and the systems that deliver them were kept in separate locations.

Nuclear weapons deployed for operation

The report claims that this is the first time that India's weapons stockpile has been considered operationally deployed, rather than just stored. Deploying ready-to-use nuclear weapons in underground missile silos and new nuclear submarines indicates increased preparedness.

India made changes in decades old policy

According to the report, the 12 warheads recently deployed mark the first time that India has integrated nuclear warheads with a delivery system or deployed them at a base with operational forces. This marks a change in its decades-old policy of keeping nuclear weapons in separate storage facilities.

PM Modi's visit to France fixed to attend G7 Summit

Suspense continues on meeting Donald Trump

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi will be on a seven-day foreign tour from June 13. During this time he will go to Slovakia. Apart from this, it has also been decided that he will go to France to attend the G-7 summit. This visit has been confirmed by the Ministry of External Affairs. They will be in Nice, France on June 13 and 14. PM Modi's visit to G-7 is also important because US President Donald Trump can also attend this summit. In such a situation, the most important thing will be whether there will be bilateral talks between PM Modi and Donald Trump or not. If this meeting of PM Modi and Donald Trump takes place during the G-7 summit in France, then this will be the first meeting of these two global leaders after February 2025. Let us tell you that during G7, Prime Minister Modi will discuss various global issues with the leaders of G7 countries and heads of international organizations. In the meeting with the leaders of G-7 countries, topics like new global partnership model, strengthening international solidarity, balanced economic development and safe and effective use of Artificial Intelligence will be the main topics of PM Modi. It is noteworthy that last week itself Donald Trump has also confirmed that he is going to go to France. There is a lot of speculation about the possible meeting between Modi and Trump but it has not been officially confirmed yet by the Ministry of External Affairs.

Fear of AI started troubling even dragons

Chinese army calls AI the biggest threat

New Delhi: China's People's Liberation Army (PLA), one of the world's largest armies, has issued a shocking warning and this warning is not about any enemy, but about their own Artificial Intelligence. An article published in PLA Daily, the PLA's official newspaper, said that excessive use of AI in the battlefield could become an extremely dangerous problem. According to the article, the dangers of overuse of AI in the military are greater than

in everyday life, as it could systematically destroy the cognitive chain of warfare, the quality of command decisions, and the potential for human-machine collaboration. According to PL Daily, AI can complicate immediate decision making and can be used to distort assessments and ignore alternatives to justify predetermined decisions. In simple words, if a commander is adamant on a wrong strategy and the AI keeps telling him the right one, then the entire army will move in the wrong direction. Such a mistake on the battlefield can cost thousands of lives.China may be at the forefront of the AI arms race, but Beijing has repeatedly said that AI should not replace humans in battlefield decision-making.

LIC
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
"With you in life, and after life"

POPULAR LIC PLANS:
- Jeevan Labh — Limited Premium, High Returns
- New Children's Money Back — Secure Your Child's Future
- Jeevan Umang — Whole Life Cover + Pension Benefits
- Bima Jyoti — Guaranteed Additions, Safe Growth
- Also Available – Complete Financial Planning Guidance

KEY BENEFITS:
- Life Insurance + Savings Plan
- Child Education and Marriage Planning
- Retirement Planning
- Tax Benefits Available

भारतीय जीवन बीमा निगम
"जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी"

FREE POLICY CONSULTATION

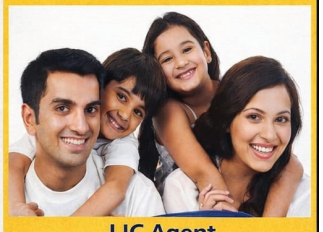

LIC Agent
Archana Shukla
+91 91129 39085
+91 74998 67628
Shop No. 2, Near Vithal Mandir, New Vadavali Chowk, Badlapur (West) – 421503
LIC Agent ID: 04497939

PUPILS TIMES
Core Committee
Anurag Shukla
Chief Editor
Shivprakash Pandey
Chief Publisher
Vikas Maurya
Co Publisher
Address: Shop No. 3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503
Contact: 9004331751
Web: pupilstimes.com

(The editor does not necessarily agree with the news, articles, and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai courts.)

Printed, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **SOMANI PRINTING PRESS Printing Press,** UNIT NO.04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E) , MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at:** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA)
Editor - **ANIL MISRA** Mob: **92208 68564** **Email:** anilmisrapc@gmail.com **PRGI. No.: MHMUL/25/A2419**